

शंखनाद और उलुध्वनि से गुंजायमान हुआ बंगाली नववर्ष पोइला बोइशाख



संगीत, कविता, लोकगीत और नृत्य-नाटिका की रंगारंग प्रस्तुति

भोपाल । भोपाल के बंगाली समुदाय के सांस्कृतिक प्रेमियों ने 1432वें बंगाली नववर्ष पोइला बोइशाख को उत्साह और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर कोलार रोड स्थित अरुणोदय हॉल में आयोजित कार्यक्रम एशो रे बोइशाख



शासनकाल से जुड़ी है। यह दिन केवल नववर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक शंखनाद और उलुध्वनि से हुई, जिससे पूरा वातावरण उत्सवधर्मी और मंगलमय हो गया। बंगाली संस्कृति में उलुध्वनि महिलाओं द्वारा जीभ और गालों के कंपन से उत्पन्न तीव्र ध्वनि को



शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सुख-शांति लाने वाली मानी जाती है। रवींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कविताओं एशो हे बोइशाख, आकाश भोरा शूजों तारा, आलो आमार आलो का समवेत पाठ हुआ, जिसमें इन्द्राणी, स्वस्तिका, तापस, मधुछंदा, देवाशीष, मालिका और तनुश्री ने भाग लिया। इसके अलावा, महुआ बोस ने ओगो

चक्रवर्ती ने ओकटोपैड पर संगत दी। कार्यक्रम का संचालन स्वस्तिका चक्रवर्ती ने कुशलता से किया। इस आत्मीय और घरेलू वातावरण में सजे इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसका आयोजन किसी संस्था द्वारा नहीं, बल्कि रूपक और महुआ बोस की अगुआई में समुदाय के लोगों ने मिलजुलकर किया एक सच्चा लोकोत्सव, जो दिल से निकला और दिलों तक पहुंचा।

शारदा मठ श्री नारायण गुरु मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से

भोपाल । माँ शारदा की पावन कृपा से यह सूचित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री नारायण मिशन द्वारा द्वितीय वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव (पंचलोहा प्रतिष्ठा) का आयोजन 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शारदा मठ श्री नारायण गुरु मंदिर परिसर, श्री नारायण नगर, ओल्ड सुभाष नगर, गोविंदपुरा, भोपाल में किया जा रहा है। यह पाँच दिवसीय भव्य महोत्सव श्री नारायण मिशन युवा शाखा की सक्रिय भागीदारी से संपन्न होगा। सभी पूजन-विधियों एवं अनुष्ठान केरल से पधारे प्रतिष्ठित आचार्य श्री राजेश तांत्रिकाल, मानपारा एवं श्री संतोष शांति काल, श्री नारायण गुरु मंदिर द्वारा विधिपूर्वक सम्पन्न किए जा रहे हैं। श्री नारायण मिशन के अध्यक्ष श्री प्रकाशानन एस ने सभी सदस्यों एवं अनुयायियों से आग्रह किया है कि वे इस पवित्र एवं ऐतिहासिक अवसर पर सपरिवार उपस्थित होकर माँ शारदा की दिव्य कृपा का लाभ लें और सामूहिक रूप से इस आयोजन को सफल बनाएं। हम समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि इस आध्यात्मिक पर्व में भाग लेकर अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बनाएं।

शालाओं में 22 अप्रैल को होगा पृथ्वी दिवस का आयोजन

भोपाल । प्रदेश की सभी शालाओं में 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन के संचालन के लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘इको क्लब फॉर मिशन लाइफ’ कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जा रही हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए विद्यालयों में इको क्लब का गठन भी किया गया है। प्रदेश में विद्यालयों में गठित इको क्लब से फ्लोरा (वनस्पति) के लिए क्यूआर कोड नामक एक शैक्षिक पहल की शुरुआत की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास करना, क्यूआर कोड निर्माण और डिजिटल जानकारी प्रदान करना है। पृथ्वी दिवस के आयोजन में विद्यालय द्वारा ‘इको क्लब फॉर मिशन लाइफ’ पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। विद्यालय के इको क्लब प्रभारी द्वारा विद्यार्थियों के समूह बनाए जाकर स्कूल परिसर एवं आस-पास के बाग बगीचों इत्यादि में उपलब्ध पेड़-पौधों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार की जायेगी। विद्यार्थी सूची अनुसार पेड़-पौधों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर डिजिटल डेटाबेस भी तैयार करेंगे। इसके आधार पर प्रत्येक पेड़-पौधों के लिए स्थिर (स्टैटिक) क्यूआर कोड बनायेंगे। क्यूआर कोड वाले लेबल को विद्यार्थियों द्वारा संबंधित पेड़ पौधों के समक्ष प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे अन्य विद्यार्थी एवं जन सामान्य भी उस पेड़ पौधे से संबंधित जानकारी सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। क्यूआर कोड में उस पेड़ पौधे से संबंधित जानकारी यथा पेड़ (फ्लोरा) का नाम एवं स्थानीय नाम, पेड़ का वैज्ञानिक नाम, पेड़ का प्रकार, फलदार / औषधि / सजावट / अन्य, वनस्पति के बारे में जानकारी जैसे पोषण मूल्य, लाभ, उपयोग आदि भी उपलब्ध होगी।

आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने किया मॉक अभ्यास

भोपाल । भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने, रासायनिक औद्योगिक आपदा पर मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने तथा जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। भोपाल सहित प्रदेश के 10 जिलों में रासायनिक औद्योगिक आपदा पर आधारित मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। मॉकड्रिल में स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा स्वास्थ्य आकस्मिकता की स्थिति में जीवन रक्षक कौशल का प्रदर्शन किया गया। जिसमें रासायनिक गैसों, केमिकल्स के रिसाव की स्थिति में बचाव के उपाय, सावधानियों, प्राथमिक उपचार, रेफरल प्रोटोकॉल, सीपीआर इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सकीय दल, पैरामेडिकल स्टाफ 108 एम्बुलेंस मौजूद रही। जिन्होंने निश्चित समय सीमा में प्राथमिक उपचार एवं रेफरल को प्रदर्शित किया। इस ड्रिल का उद्देश्य प्रतिक्रिया रणनीतियों को परिष्कृत करना और आपदा प्रबंधन हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल में प्रत्येक परिदृश्य को वास्तविक जीवन की आपात स्थितियों को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि उच्च तनाव की स्थितियों में तैयारियों का परीक्षण किया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि अमोनिया एवं अन्य जहरीली गैसों के रिसाव में समय पर उपचार आवश्यक होता है। संयुक्त अभ्यास में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिनिमम रिसपांस टाइम में चिकित्सा सेवाओं की प्रदायगी का अभ्यास प्रदर्शन किया।

जैन मंदिर तोड़ने के विरोध में जैन समाज ने दिया मौन धरना

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई स्थित विले पार्ले पूर्व की कांवली वाड़ी जैन मंदिर को तोड़ने और नीमच मध्य प्रदेश मे जैन संतों पर हमले के विरोध में शनिवार 19 अप्रेल को मंगलवारा जैन मंदिर के बाहर प्रातः 9 से 10 बजे सांकेतिक मौन धरना मुंबई में जैन मंदिर को नगर महापालिका द्वारा ध्वस्त किये जाने और नीमच में पिछले दिनों जैन संतों पर हमले के विरोध में जैन समाज भोपाल एवं मंगलवारा जैन समाज द्वारा शनिवार 19 अप्रेल को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक सांकेतिक मौन धरना दिया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए मंगलवारा जैन मंदिर के अध्यक्ष आदित्य मनाया विजय श्वेता राकेश नायक महेद्र जैन हुण्डी पिन्टु जैन मनोज ठेकेदार अशोक अजमेरा,सुरेद्र परसोन ने बताया कि उक्त घटनाओं से सम्पूर्ण भारत की जैन समाज में रोष व्याप्त है। हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं तथा



एक ज्ञापन मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय को प्रेषित करते हुए धरने के समापन पर प्रसासनिक अधिकारी को दिया जायेगा। धरने में पंकज प्रधान सुनील सिधई, सुनील लिवांस,शैलेन्द्र प्रधान, डबल्टर अनुराग जैन मनोज जैन मन्तु, बन्टी अजमेरा, प्रमोत अजमेरा,राजेश जैन इतवारा पदम जैन बैक,कौशल जैन,जयेश जैन अशोक अजमेरा,

भविष्य जैन, सौरभ हुण्डी,सुरेद्र चौधरी पवन चौधरी तथा महिला मंडल अध्यक्ष नीता जैन श्रीमती सरोज जैन, अनीता जैन, रंजना जैन मंजू जैन रेखा जैन, रजनी जैन, रश्मि जैन, सोना जैन , तारा जैन, सुशीला जैन पूजा जैन, आभा अजमेर मनोरमा अजमेर, रतन जैन, प्रतिभा जैन, सपना जैन, रजनी जै, जिज्ञासा जैन आदि शामिल रहे।

विकास कार्यों में लापरवाही नहीं चलेंगी, अधिकारियों को समय पर करना होगा पूरा काम: कृष्णा गौर

राज्यमंत्री ने गोविंदपुरा क्षेत्र के वार्ड-61 में भ्रमण कर रहवासियों की समस्याएं सुनीं

भोपाल । पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही कई बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को समय पर काम करना होगा। जिम्मेदार अधिकारियों के लंबे समय तक विभागों में फाइल अटकाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शुक्रवार को वार्ड-61 में औचक निरीक्षण कर रहवासियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही उनका निराकरण किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने भ्रमण के दौरान कहा कि नागरिक सुविधाओं के स्थायी समाधान के लिए हम संकल्पित हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड-61 में भ्रमण की शुरुआत श्री शिव मंदिर निर्मल पैलेस से की।



यहां पर स्थानीय रहवासियों ने पेयजल से जुड़ी कुछ परेशानियाँ बताईं। स्थानीय नागरिकों ने पानी का प्रेशर कम होना और निर्धारित समय से कम अवधि तक पानी मिलने की शिकायत की। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन का प्रेशर ठीक करने, पानी लाइन के नेटवर्क को दुरुस्त करने और जल आपूर्ति की समय सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए। लवकुश नगर, समृद्धि परिसर खजूरीकलां के रहवासियों ने कहा कि यहां मौजूद 40 फीट रोड पर बारिश में पानी भर जाता है। रहवासियों ने नाली पर से अतिक्रमण हटा कर

सफाई की मांग की। राज्यमंत्री ने तुरंत ही अधिकारियों से पानी निकासी की व्यवस्था बनाने और मंदिर में पविल ब्लॉक लगाने के निर्देश दिए हैं। रचना विहार एवं अवंतिका विहार में रहवासियों ने कॉलोनी की प्रस्तावित सड़क

एवं पार्क सौंदर्यीकरण कार्यों के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण पूर्णता हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य हेतु विधायक निधि से 25 लाख की सहयोग राशि प्रदान की गई है, ताकि धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का स्वरूप और अधिक आकर्षक बन सके। तुलशी परिसर में मार्ग चौड़ीकरण, नाला सफाई, सीवेज के खुले में बहने तथा मंदिर सौंदर्यीकरण को लेकर नागरिकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को गम्भीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को इन सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।

विश्व लीवर दिवस - अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और नियमित रूप से योग अभ्यास करें - योग गुरु महेश अग्रवाल



भोपाल । आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड भोपाल के योग गुरु महेश अग्रवाल ने बताया कि लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क को छोड़कर लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं, जिसमें दवा भी शामिल है, लीवर से होकर गुजरता है। आप लीवर के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह एक ऐसा अंग है, जिसकी अच्छी देखभाल न करने पर यह आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। यह हमारे पेट के दाहिने और स्थित है लीवर की अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे जिगर, यकृत आदि। यदि यकृत काम करना बंद कर दे तो एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसका वजन 2.5 से लेकर 3 पौंड तक हो सकता है। लीवर हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाओं को करने में मदद करता है। यह एक कशेरुक या रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में मौजूद होता है। चयापचय में भी मदद करता है। यह वसा को जलाने में मदद करता है और शरीर के वजन को बनाए रखता है।

गांधीसागर में फिर गूजेगी चीतों की दहाड़, कल मुख्यमंत्री डॉ. यादव छोड़ेंगे दो नर चीते

कूनों को बनेगा आदर्श वन्य पर्यटन स्थल, उद्यान परिक्षेत्र में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए खोले जाएंगे दीदी कैफे

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इको सिस्टम के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मध्यप्रदेश में वृहद स्तर पर काम हो रहा है। वन्य पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था को गति देता है और अब यही हमारी समृद्धि का प्रवेश द्वार बन रहा है। हमारी सरकार कूनों राष्ट्रीय उद्यान को एक आदर्श वन्य प्राणी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। प्रदेश में सिर्फ कूनों ही नहीं, अब मंदसौर जिले का गांधीसागर अभयारण्य भी चीतों से गुलजार होगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से आगामी 20 अप्रैल को गांधी सागर अभयारण्य में चीते छोड़े जाएंगे। कड़ी सुरक्षा में कूनों नेशनल पार्क से 2 चीते शिफ्ट कर गांधीसागर अभयारण्य में ले जाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कूनों नेशनल पार्क में पर्यटन तेजी से बढ़े, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ग्वालियर से कूनों के लिए डायरेक्ट रोड और एयर कनेक्टिविटी भी विकसित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को समल भवन (मुख्यमंत्री निवास) में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर हर्ष व्यक्त किया कि भारत (मध्यप्रदेश) में जन्में चीता शावकों की जीवन प्रत्याशा (सर्वाइवल रेट) पूरे विश्व में सर्वाधिक है। दूसरे देशों में चीता शावक जलवायु से अनुकूलन के अभाव में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चीतों के लिए जरूरी जलवायु और वातावरण की दृष्टि से गांधीसागर अभयारण्य बेहद अनुकूल है, इसलिए सरकार यहां चीते छोड़कर इस अभयारण्य को भी चीतों से गुलजार करेगी।

कूनों जुड़ेगा रोड टू एयर कनेक्टिविटी से: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ मिलकर सबके सहयोग से हम चीतों का पुनर्वास करेंगे। ग्वालियर से कूनों नेशनल पार्क तक पक्की बारहमासी रोड बनाई जाएगी। कूनों में टेंट सिटी तैयार कर यहां आने वाले पर्यटकों को जंगल में प्रकृति के पास समय बिताने का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री यादव की मंशा के अनुरूप हम कूनों प्रक्षेत्र में इंटरनेशनल

लेवल का एक पशु चिकित्सालय और रेस्क्यू सेंटर भी खोलेंगे। इसके लिए सरकार से भी मदद लेंगे। पशु चिकित्सालय के संचालन से कूनों के चीतों के इलाज के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र में गौरवश के उपचार में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नेचर टूरिज्म सेक्टर में निहित असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगी। राज्य के अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को वन्य पर्यटन से जोड़ेगा। चीता मित्र और महिला स्व-

सहायता समूह की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड भी बनाएंगे, कूनों परिक्षेत्र में राज्य आजीविका विकास मिशन से दीदी कैफे संचालित किए जाएंगे, जिससे चीता मित्रों और महिलाओं को स्थानीय रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

सरकार किंग कोबरा और दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का भी करेगी संरक्षण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की धरती पर चीतों के पुनर्वास से एक सदी का इंतजार खत्म हुआ है। राज्य सरकार किंग कोबरा, घड़ियाल और दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार किंग कोबरा संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेश के जंगलों में जहरीले सांपों की संख्या नियंत्रित करने के लिए किंग कोबरा को बसाना आवश्यक है। पहले चरण में 10 किंग कोबरा मध्यप्रदेश लाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन अधिकारियों को चंबल नदी से घड़ियाल और कछुओं को प्रदेश की पुर्नर्वासित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में बड़ी क्षमताएं विद्यमान हैं। उन्होंने कूनों में चीतों के पुनर्वास और वन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री यादव ने वन्य प्राणियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में चल रहे वन्य प्राणियों की पुनर्वास परियोजनाओं की देखरेख के लिए वन, पर्यटन, पशु चिकित्सा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक टास्क फोर्स



बनाया जाए। यह टास्क फोर्स नियमित रूप से सभी प्रोजेक्ट्स की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले के 80 गांवों के 400 चीता मित्रों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय वन

प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल के साथ अनुबंध कर सकते हैं। चीता मित्रों को होम स्टे के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें नेचर टूरिज्म के लिए तैयार करने की दिशा में भी कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कूनों के आसपास स्थित ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जाए।

कूनों में मौजूद एक पुराने किले को हेरिटेज वॉक के रूप में विकसित किया जा सकता है। मगरमच्छ और घड़ियाल के दीदार के लिए व्यू प्वाइंट्स बने, वन्य प्राणियों के रेस्क्यू के लिए सेंटर और पर्यटकों के लिए आयुर्वेदिक सेंटर तैयार किए जाएं। केन्द्रीय वन मंत्री यादव ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कूनों समेत प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा जाए। देश-विदेश से कूनों आने वाले पर्यटकों को आवास, भोजन, स्वच्छता से जुड़ी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अगर सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी, तो निश्चित रूप से दुनिया से टूरिस्ट चीता देखने के लिए पर्यटक कूनों नेशनल

पार्क और गांधीसागर अभयारण्य आएंगे। बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से बताया गया कि देश में चीता प्रोजेक्ट पर अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है।

इसमें से 67 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश में हुए चीता पुनर्वास पर व्यय हुई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत ही अब गांधीसागर अभयारण्य में भी चीते चरणबद्ध रूप से विस्थापित किए जाएंगे। गांधीसागर अभयारण्य राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अभी कूनों और गांधीसागर अभयारण्य में चीता मित्रों की क्षमता संवर्धन के लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।

बैठक में चीता प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तन्मय कुमार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी, अतिरिक्त महानिदेशक टाइगर प्रोजेक्ट एवं सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) डॉ. गोविंद सागर भारद्वाज, अंतरिम महानिदेशक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) एस.पी. यादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक एनटीसीए संजयन कुमार, उप वन महानिदेशक एनटीसीए वैभव सी. माथुर एवं उप वन महानिदेशक (वन्यजीव विभाग) केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अंजन कुमार मोहंती सहित अपर मुख्य सचिव वन अशोक

प्रसाद योजना से संवरेगी माँ पीताम्बरा की नगरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माँ पीताम्बरा की नगरी को प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनने के लिये सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत मंदिर परिसर और उससे जुड़े क्षेत्र के विकास के लिए 44.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना से धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति और प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पीतांबरा पीठ में पर्यटन सेवाओं के विस्तार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सुविधाएं बढ़ने से यह विकास तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। हाइवे से मंदिर की ओर लगभग 2 कि.मी. के मार्ग पर पैदल आने वाले दर्शनार्थियों एवं वरिष्ठ जनों को ताजी हवा, खुला वातावरण और आराम प्रदान करने के लिए विशेष रूप से खुले स्थानों का विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों में हरियाली, बेंच, पेड़-पौधे और विश्राम करने के लिए स्थान होंगे। इससे पर्यटकों को ताजगी का अनुभव होगा। शहर के नागरिकों और पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। इससे शहर अधिक सुविधाजनक और सुगम बनेगा। मंदिर प्रबंधन ने उत्तर गेट के समीप इसके लिये लगभग 1000 वर्ग मी. की भूमि उपलब्ध कराई है, उत्तर गेट भविष्य का मुख्य द्वार होगा। उत्तर द्वार से मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर (व्याख्या केंद्र) बनाया जाएगा।

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद हाउसिंग बोर्ड की वरिष्ठ लेखा अधिकारी को हटाया

भोपाल। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की लेखा शाखा में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी अल्पना ओझा को उनके पद से हटाया गया है। यह निर्णय निर्माण कार्यों से जुड़े भुगतान में कथित लापरवाही और आर्थिक नुकसान की शिकायतों के बाद लिया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए ओझा को उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त कर कोष एवं लेखा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि ओझा पर लंबे समय से निर्माण से संबंधित बिलों के भुगतान में देरी और प्रक्रिया में अनावश्यक अड़चनों के आरोप थे। इस मामले में शिकायत लोकायुक्त कार्यालय तक पहुंची थी, जहां प्रारंभिक स्तर पर गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच की सफािशरी की गई। वित्त विभाग की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल, इस मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता बताई गई है और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण भुगतान प्रक्रियाओं को समयबद्ध और नियमसम्मत ढंग से संपन्न किया जाए।

एमपी में शिक्षक चयन परीक्षा कल से, 1 लाख 60 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 अप्रैल रविवार से शुरू होगी। परीक्षा में लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से नकल करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) आयोजित कर रहा है। परीक्षा 29 अप्रैल तक चलेगी। ईएसबी ने विषय वार परीक्षा की समय-सारिणी घोषित कर दी है। इसमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक (गायन, वादन व नृत्य) के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षक (विषय) के लिए परीक्षा होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित होगी। इसमें 1.60 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पाली में होगी। इसमें पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ से 11 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पालीकी परीक्षा दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने के तीन दिन पहले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण

भोपाल। प्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में इन बिन्दुओं को केन्द्रित करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रत्येक जिले में जन भागीदारी से संचालन किया जा रहा है। छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान पर जन अभियान परिषद छात्र-छात्राओं के सहयोग से जल का महत्व समझाने के लिये दीवार लेखन करा रही है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम कार्यक्रम में बीएस डब्ल्यू- एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राओं के द्वारा सेक्टर क्रमांक 02 विकासखण्ड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला एवं जुन्नारदेव दमामी, जिवर नगरी मंदिर परिसर में अंतर्गत जल है तो कल है, जल ही जीवन है, हम सबने बना है, पानी को बचाना है सहित विभिन्न प्रकार के नारों का दीवार लेखन के माध्यम से ग्रामीणों जनों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

तालाबों का संरक्षण और गहरीकरण भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक: खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना जिले के ग्राम सागर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत तालाब गहरीकरण में सहभागिता कर श्रमदान किया। मंत्री राजपूत ने पूजा कर गेती-फावड़ा लेकर स्वयं श्रमदान करते हुए तालाब गहरीकरण की शुरुआत की और जल संरक्षण की इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाई। मंत्री श्री राजपूत और विधायक प्रियंका पेंची ने ग्रामीणों से संवाद कर जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री राजपूत ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयास नहीं बल्कि जन-सहभागिता से जुड़ा एक संकल्प है। तालाबों का संरक्षण और



संरक्षण की इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाई। मंत्री श्री राजपूत और विधायक प्रियंका पेंची ने ग्रामीणों से संवाद कर जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री राजपूत ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयास नहीं बल्कि जन-सहभागिता से जुड़ा एक संकल्प है। तालाबों का संरक्षण और

गहरीकरण हमारे भविष्य की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से इस अभियान को जनांदोलन के रूप में अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उज्जैन में जल-जागरण की ऐतिहासिक शुरुआत, गंधर्व सागर में हुआ भूमिपूजन

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

जल गंगा संवर्धन अभियान में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की भूमि उज्जैन आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब गंधर्व सागर के भूमि पूजन के साथ जल-जागरण की क्रांति का विधिवत शुभारंभ हुआ।

यह आयोजन केवल एक परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति राष्ट्रव्यापी जन-जागरण की पहली औपचारिक आहुति बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा महाकाल के स्मरण, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के साथ हुई। पूरे वातावरण में देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का संचार हुआ। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत यह आयोजन एक जन-आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसका उद्देश्य केवल जल स्रोतों का



पुनरुद्धार नहीं, बल्कि नागरिकों में जल प्रबंधन और संरक्षण की भावना जाग्रत करना भी है। वक्ताओं ने इस अभियान को जनभागीदारी की मिसाल बताते हुए कहा कि जल ही जीवन है। अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह जन-आंदोलन बन चुका है। गंधर्व सागर का पुनरुत्थान

उज्जैन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को जल संकट से उबारने की दिशा में एक तो कल इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इस चेतावनी के साथ सभी को जल गोवर्धन सागर, पुरुषोत्तम सागर, पुष्कर सागर, विष्णु सागर और क्षीर सागर का उल्लेख करते हुए उनकी धार्मिक और

सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित किया गया। अगर आज जल नहीं बचाया गया, तो कल इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इस चेतावनी के साथ सभी को जल गोवर्धन सागर, पुरुषोत्तम सागर, पुष्कर सागर, विष्णु सागर और क्षीर सागर का उल्लेख करते हुए उनकी धार्मिक और

सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित किया गया। अगर आज जल नहीं बचाया गया, तो कल इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इस चेतावनी के साथ सभी को जल गोवर्धन सागर, पुरुषोत्तम सागर, पुष्कर सागर, विष्णु सागर और क्षीर सागर का उल्लेख करते हुए उनकी धार्मिक और

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में टेली मेडिसिन सेवा का किया शुभारंभ



भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि टेली-मेडिसिन सेवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं के प्रदाय का सशक्त माध्यम है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में टेली-मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा से रीवा और सोधी जिलों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों को वरिष्ठ विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त होगा। इस सेवा के तहत अब संजय गांधी अस्पताल, रीवा के मेडिसिन, शिशु रोग (पेडियाट्रिक्स) तथा स्त्री रोग (गायनी) विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को फोन या अन्य संचार माध्यमों से जरूरी परामर्श देंगे। इससे उन मरीजों को तुरंत लाभ मिलेगा जिन्हें विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में ही पड़ेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह सेवा न सिर्फ मरीजों की यात्रा की आवश्यकता को कम करेगी, बल्कि समय, धन और संसाधनों की भी बचत करेगी। साथ ही, इससे प्राथमिक स्तर पर कार्यरत चिकित्सकों को विशेषज्ञों की मदद से त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान व इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि टेली-मेडीसिन सेवा का प्रभावी उपयोग सशक्त व स्वस्थ मध्यप्रदेश के विजन को धरातल पर उतारने में सहयोगी होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने टेली-मेडिसिन कक्ष की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं विधिवत संचालन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। डीन मेडिकल कॉलेज रीवा डॉ. सुनील अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार: नवाचार श्रेणी के लिए चयनित अधिकारियों की सूची जारी

इन्दौर। सामान्य प्रशासन विभाग ने नवाचार श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 चयनित शासकीय अधिकारियों की सूची जारी की है। सूची में 6 क्षेत्रों के लिए 14 शासकीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सभी चयनित शासकीय सेवकों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1 लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। अधिकारियों को यह पुरस्कार अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचार के लिए दिया जा रहा है। सम्मान समारोह का आयोजन नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में किया जाएगा। शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण, अधोसंरचना, नागरिक सेवा प्रदाय-सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन, रोजगार एवं आर्थिक विकास क्षेत्रों में नवाचार के लिये पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं। पुरस्कार के चयनित अधिकारियों में सुश्री शीला दाहिमा, माधव प्रसाद पटेल, अदिति गर्ग, डॉ. इंदिरा दांगी, शारदा डुडुवे, आलोक पौराणिक, चंद्रमोहन ठाकुर, डॉ. यशपाल सिंह, संजय जोशी, अनित तोमर, श्रवण गुप्ता,गणेश शंकर मिश्रा, दिव्यांक सिंह और प्रवीण सिंह के नाम शामिल हैं।

हिनौती गोधाम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि हिनौती गोधाम में गौरवशों के लिए शेड की व्यवस्था सहित चारा व पानी सुविधा सुनिश्चित कराएंगे। गोधाम में पानी की कमी न होने पाये इस पर विशेष ध्यान दें। सर्किट हाउस राजनिवास में हिनौती गोधाम के संबंध में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास के कार्यों सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिनौती गोधाम में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराये तथा गोवंश के लिए पशु आहार की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराये। उन्होंने कहा कि गोधाम में व्यवस्था के अनुरूप ही गौरवंश संरक्षित रखे जाय। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की धीमी प्रगति व व्यवस्थाओं में कमी होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा



एसडीएम को निर्देश दिये कि प्रतिदिवस हिनौती गोधाम जाकर व्यवस्थाओं की मानीटरिंग करें। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, अध्यक्ष गंगेव जनपद विकास तिवारी, एसडीएम राजेश सिन्हा, समाजसेवी राजेश पाण्डेय, उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. राजेश मिश्रा उपस्थित रहे।

संपादकीय

वक्फ संशोधन पर सर्वोच्च

अदालत के सवाल

सर्वोच्च अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर ‘अंतरिम आदेश’ जारी करने के मुड़ में है, लेकिन कानून पर फिलहाल रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। नए कानून की संवैधानिकता को चुनौती देती 73 से अधिक याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने हैं। कुछ सवाल न्यायिक पीठ ने भी उठाए हैं, लेकिन वे वक्फ से जुड़े विवादों पर चिंतित भी हैं। प्रधान न्यायाधीश ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़कती-सुलगती हिंसा पर परेशानी और हैरानी जताई। अंतत उन्होंने अपील के स्वर में कहा- ‘मामला सर्वोच्च अदालत के सामने है, लिहाजा हिंसा बेमानी है। हिंसा नहीं की जानी चाहिए।’ बहरहाल सर्वोच्च पीठ की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही। पीठ ने ‘वक्फ बाय यूजर’ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और दो सप्ताह में उसका जवाब मांगा है। नए कानून में जो प्रावधान तय किए गए हैं, न्यायिक पीठ उनसे सहमत नहीं लगती। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं-14वीं सदी की हैं। आप ऐसे ‘वक्फ बाय यूजर’ को कैसे रजिस्टर करेंगे? वे दस्तावेज कहाँ से दिखाएंगे? यह असंभव है। यदि वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को ‘डी-नोटिफाई’ किया जाता है, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। न्यायिक पीठ का तीन मुद्दों पर मूड स्पष्ट दिखाई दिया। एक, अदालत से वक्फ घोषित संपत्ति ‘डी-नोटिफाई’ नहीं होगी। वह वक्फ बाय यूजर हो अथवा वक्फ बाय डीड हो। दूसरा, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे कर सकते हैं, लेकिन वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। अदालत को सूचित करेंगे। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को लेकर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस खन्ना और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई। न्यायमूर्ति ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड या मंदिरों के प्रबंधन में किसी मुसलमान को शामिल करेगी? यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल ने न्यायिक पीठ के तीनों न्यायाधीशों के धर्म (हिंदू) पर सवाल उठाया। प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया- ‘जब हम इस सीट पर बैठते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती। कानून के सामने सभी पक्ष एकसमान हैं।’ अब यदि सर्वोच्च अदालत कोई अंतरिम आदेश जारी करती है, तो उसमें कुछ निर्देश सरकारी कानून के खिलाफ भी हो सकते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल बार-बार अनुच्छेद 26 और 20 करोड़ लोगों की आस्था और उनके धार्मिक प्रबंधन के अधिकार का मुद्दा उठा रहे थे, तो प्रधान न्यायाधीश ने साफ कहा कि अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष है। यह विधायिका को कानून बनाने से नहीं रोकता। यह सभी समुदायों पर लागू होता है। संसद ने हिंदुओं के संदर्भ में भी कानून बनाए हैं। न्यायमूर्ति ने सिब्बल को धार्मिक बातें कहने से रोका। सिब्बल ने ही ‘अंतरिम आदेश’ की मांग की थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रधान न्यायाधीश ने उसे भी खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि जामा मस्जिद सरीखी स्मारक इमारतें यथावत रहेंगी। उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जस्टिस खन्ना ने वक्फ संशोधन कानून की धारा 2-ए के प्रावधान पर चिंता जताई। इतना तो स्पष्ट लगता है कि न्यायिक पीठ वक्फ कानून को खारिज नहीं करेगी और रोक लगाने के भी आसार नगण्य हैं, लेकिन ऐसे कुछ सुधार करवा सकती है, जो संविधान के मद्देनजर न्यायोचित नहीं हैं।

2014 से 15 प्रतिशत बढ़े प्राइवेट स्कूल, लगातार बढ़ा रहे फीस

डॉ. ज्ञान पाठक

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों की फीस में की गयी अत्यधिक वृद्धि को लेकर जो विवाद छि? है, उससे देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में और भी भयावह जानकारी मिलती है। सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है और शिक्षकों तथा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उनमें शिक्षा की स्थिति खराब होती जा रही है। इससे प्राइवेट स्कूलों के पनपने और समृद्ध होने के लिए परिस्थितियाँ बनती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमेशा से देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है - 2014-15 से 2023-24 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी गैस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, पिछले एक दशक के दौरान देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आयी है, जिनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में हैं।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों की फीस में की गयी अत्यधिक वृद्धि को लेकर जो विवाद छि? है, उससे देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में और भी भयावह जानकारी मिलती है। सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है और शिक्षकों तथा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उनमें शिक्षा की स्थिति खराब होती जा रही है। इससे प्राइवेट स्कूलों के पनपने और समृद्ध होने के लिए परिस्थितियाँ बनती हैं, जो केवल उन्हीं छात्रों को शिक्षा देते हैं जिनके माता-पिता या अभिभावक आर्थिक रूप से संपन्न हैं या कम से कम जो किसी तरह से फीस वहन कर सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल से। यह इस देश के बच्चों के सार्वभौमिक और समान शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है और

षडयंत्रकारी नासिक कलेक्टर को गोली मारी थी

रमेश शर्मा

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अनंत वीरों का बलिदान हुआ है। कुछ के तो नाम तक नहीं मिलते और जिनके नाम मिलते हैं उनका विवरण नहीं मिलता । नासिक में ऐसे ही क्रांतिकारियों का एक समूह था जिनमें तीन को फाँसी और दो को आजीवन कारावास का वर्णन मिलता है । अन्य किसी का नहीं। इसी समूह में तीन बलिदानी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फाँसी दी गई। इनमें विनायक नारायण देशपांडे और कृष्ण गोपाल कर्वे का विवरण न के बराबर मिलता है ।उन दिनों नासिक में एक कलेक्टर जैक्सन आया । वह संस्कृत और भारतीय ग्रंथों का कथित जानकार था । वह चर्च से जुड़ा था । उसने प्रचारित किया कि वह पूर्व जन्म में संत था । उसका लक्ष्य भारतीय जनजातियों और असुसुचित समाज पर था । वह ग्रंथों पर आधारित कथाओं के उदाहरण देते और उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करता । उसके लिये अधिकारियों की एक टीम उस का प्रचार का कार्य कर रही थी । इससे क्षेत्र में सामाजिक दूरियाँ बढ़ने लगीं और धर्मान्तरण होने लगा । मतान्तरण रोकने और समाज में स्वत्व जागरण के लिये गणेश सावरकर जी ने युवकों का एक समूह तैयार किया । इसमें अनंत कान्हेरे, श्रीकृष्ण कर्वे और विनायक देशपांडे जैसे अनेक ओजस्वी युवक थे । जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में लग गये । गणेश सावरकर और इस टोली के काम से कलेक्टर सतर्क हुआ । तभी गणेश सावरकर जी ने कवि गोविंद की राष्ट्रभाव वाली रचनाएं संकलित कीं और सोलह रचनाओं का का संकलन प्रकाशित कर दिया । कलेक्टर को यह पुस्तक बहाना लगी और राष्ट्रद्रोह के आरोप में सावरकर जी बंदी बना लिये गये । यही नहीं पुलिस ने पुस्तक की तलाश का बहाना बनाकर उन सभी घरों पर दबिश दी जो उसके मतान्तरण षड्यंत्र से समाज को जाग्रत करने में लगे । तब युवकों की इस टोली ने नासिक को इस कलेक्टर से मुक्त करने की योजना बनाई। अनेक सार्वजनिक और प्रवचन के आयोजनों में प्रयास किया पर अवसर हाथ न लगा ।

अंततः अवसर मिला 21 दिसम्बर 1909 को । कलेक्टर की शान में एक मराठी नाटक का मंचन किया जा रहा था ।कलेक्टर के कार्यों से ब्रिटिश सरकार और चर्च प्रसन्न था । कलेक्टर जैक्सन को पदोन्नत कर आयुक्त बनाकर मुम्बई पदस्थ करने के आदेश हो गये । विजयानंद थियेटर में नाटक का यह मंचन उसी उपलक्ष्य में था । यही अंतिम अवसर है यह सोचकर

अपेक्षाकृत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए असमान शिक्षा स्तर बनाता है। अभिभावकों तो माता-पिता में यह डर प्राइवेट स्कूलों के प्रति उनके आकर्षण को ब?ता है।

अभी पिछले फरवरी महीने में ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा को बताया था कि 2014-15 और 2023-24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आई है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल संख्या की बात करें तो सरकारी स्कूलों की संख्या में 89,441 की कटौती की गयी, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 42,944 की वृद्धि हुई। वर्तमान में देश में 10,17,660 सरकारी स्कूल हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या 3,31,108 है।

सदन में दिये गये आंक?ों से पता चला है कि भाजपा शासित दो राज्यों- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक सरकारी स्कूल बंद किये। मध्य प्रदेश ने 29,410 सरकारी स्कूल बंद किये हैं और उत्तर प्रदेश ने 25,126 सरकारी स्कूल बंद किये हैं। इन दोनों राज्यों ने मिलकर देश में हुई कटौती में 60.9 प्रतिशत का योगदान दिया है। पिछले दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में 19,305 प्राइवेट स्कूलों की वृद्धि देखी गयी, जो देश में प्राइवेट स्कूलों की कुल वृद्धि का 44.9 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गिरावट 24.1 प्रतिशत रही, उसके बाद जम्मू-कश्मीर में 21.4 प्रतिशत, ओडिशा में 17.1 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 16.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 15.5 प्रतिशत, झारखंड में 13.4 प्रतिशत, नागालैंड में 14.4 प्रतिशत, गोवा में 12.9

कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कान्हेरे थियेटर में पहुँचे। योजना बनी कि गोली अनंत कान्हेरे चलायेंगे और शेष दोनों कवर करेंगे । उनके पास भी रिवाल्वर थे । तीनों अपने साथ विष की पुर्द्वि भी लेकर गये थे । योजना थी कि यदि पिस्तौल में गोली न बची तो विषपान कर लेंगे ताकि पुलिस जीवित न पकड़ सके । नाटक का मंचन पूरा हुआ लोग बधाई देने कलेक्टर के आसपास जमा हुये । अवसर का लाभ उठाकर ये तीनों क्रांतिकारी भी समीप पहुँचे। श्रीकृष्ण कर्वे और देशपांडे ने जैक्सन को उठाकर नोचे पटक़ा और उसके सीने पर पैर रखकर अनंत ने चार गोलियां उसके सीने में उतार दीं। जैक्सन तुरंत मार गया। वहीं उपस्थित दो अधिकारियों पलशिकर और मारुतारव ने अनंत पर अपने डंडों से हमला किया। आसपास के अन्य लोग भी टूट पड़े। इससे तीनों को न तो स्वयं पर गोली चलाने का अवसर मिला और न विषपान करने का । तीनों वहीं उपस्थित कलेक्टर समर्थक अधिकारियों के हमले से बुरी तरह घायल हो गये । उन्हें बंदी बना लिया गया । इस घटना की गूँज लंदन तक हुई । तीनों क्रांति कारियों की आयु अठारह से बीस वर्ष थी ।

इनमें अनंत कान्हेरे का जन्म 7 जनवरी 1892 को रत्नागिरी जिले के खेत तालुका के एक छोटे से गाँव अयानी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा निजमाबाद में और उनकी अंग्रेजी शिक्षा औरंगाबाद में हुई। 1908 में कान्हेरे औरंगाबाद लौट आए जहां उन्हें गंगाराम नामक एक मित्र ने क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा था । दूसरे क्रांतिकारी कृष्णजी गोपाल कर्वे का 1887 में हुआ था । उन्होंने बीए ऑनर्स का पूरा किया था मुंबई विश्वविद्यालय में एलएलबी में प्रवेश ले लिया था। वे नासिक में अभिनव भारत से जुड़े थे । जैक्सन की हत्या की योजना बनी तो इसमें शामिल हो गये । तीसरे क्रांतिकारी का परिचय बहुत ढूँढने पर भी न मिला पर फाँसी की सूची में उनका नाम है

बॉम्बे कोर्ट में मुकदमा चला 29 मार्च 1910 को इन तीनों क्रांतिकारियों को हत्या का दोषी पाकर फाँसी की सजा सुनाई गई और 19 अप्रैल 1910 को ठाणे जेल में तीनों को फाँसी दे दी गई। अधिकारियों ने तीनों के शव परिवार को भी नहीं सौंपे। जेल में ही जला दिया और अवशेष समन्दर में फेंक दिये । जैक्सन हत्याकांड में दो अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास मिला । जिनकी जेल की प्रताड़नाओं से बलिदान हुआ।

शत शत नमन इन क्रांतिकारियों को ।



उत्तर प्रदेश में 24.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तीन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां प्राइवेट स्कूलों की संख्या में गिरावट आयी, वे थे मेघालय में 5.36 प्रतिशत, एनसीटी दिल्ली में 2.88 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 0.27 प्रतिशत। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन राज्यों में सरकारी स्कूली शिक्षा की उपलब्धियां अधिक हैं, खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी स्कूल शिक्षा के मामले में पिछ?े हुए हैं, जिसके कारण वहां प्राइवेट स्कूलों का दबदबा ब?ता जा रहा है।इससे ही समझा जा सकता है कि पिछले एक दशक में देश भर में प्राइवेट स्कूलों के मामलों में अत्यधिक फीस वसूलने से ज्यादा अहमियत कैसे मिल रही है। इससे प्राइवेट स्कूल छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने में सक्षम हो जाते हैं।

एक तरफ परिवारों की वास्तविक आय में गिरावट और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वृद्धि की पुष्टभूमि में इस साल की स्थिति विशेष रूप से अभिभावकों के लिए परेशानी भरी हो गयी है।

हाल ही में लोकल सर्किल द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में पिछले तीन वर्षों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लगभग 93

प्रतिशत और उत्तराखंड में 8.7 प्रतिशत रही। प्राइवेट स्कूलों के मामले में, कुल 10 राज्यों में 14.9 प्रतिशत की औसत वृद्धि की पार कर लिया। बिहार में प्राइवेट स्कूलों में 179.14 प्रतिशत, ओडिशा में 80.36 प्रतिशत, तथा

शैक्षणिक सत्र 2025-26की शुरुआत होते ही देशभर से प्राइवेट स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही है। दिल्ली में, अभिभावकों का विरोध राजनीतिक हो गया है, क्योंकि राज्य में भाजपा सत्ता में आ गयी है और फरवरी 2025 का चुनाव हारने वाली आप विपक्ष में है। आप को सरकारी स्कूलों की शिक्षा की अधिकांश प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में कमी आयी है। आप ने प्राइवेट स्कूलों में हाल ही में की गयी फीस वृद्धि को लेकर भाजपा शासन पर हमला करते हुए दावा किया है कि सलाह? भाजपा और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ के अध्यक्ष के बीच संबंध है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के स्कूलों में अत्यधिक फीस वृद्धि हुई है। यह मुख्यमंत्रि से जुड़े हितों के टकराव का एक खुला मामला है।

आप नेता सीएच रामाद्राज ने कहा, एक ही संगठन और उसके मुखिया, जिसका मुख्य एजंडा दिल्ली भर में स्कूल फीस ब?ेती को ब?ेता देना है, भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चुनाव अभियान में शामिल थे। जवाब में, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप फरवरी के चुनाव में हार से निराश है।

देश की नवीन प्रतिभाओं के लिए नीति बनाइए

राकेश दुबे

आँकड़े सामने है कि बीते साल विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें भी अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 36 और कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में 34 प्रतिशत की कमी आई है। यही स्थिति ब्रिटेन की भी है। आंकड़े वर्ष 2024 के हैं। निश्चित तौर पर जब ट्रंप काल में उखाड़-पछाड़ के दौर के आंकड़े सामने आएंगे, तो वे ज्यादा चौंकाने वाले होंगे।

एक समय था कि छात्रों में परदेस जाकर पढ़ाई करने का जुनून उफान पर था। हर साल मां-बाप खुन-पसीने की कमाई से और अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ने के लिये विदेश भेज रहे थे। कहीं-कहीं तो खेत बेचकर और घर गिरवी रखकर बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजने के मामले भी प्रकाश में आए। देश में बेकौं से एजुकेशन लोन मिलने की सुविधा ने भी छात्रों को विदेश यात्रा को सुगम बनाया। हर साल लाखों छात्र सुनहरे सपने लिये विदेश गमन कर रहे थे। ये जुनून पंजाब में विशेष रूप से देखा गया, जो कनाडा-अमेरिका आदि देशों में संपूर्ण भारत से जाने वाले छात्रों का साठ प्रतिशत था। जरूरी नहीं था कि ये सारे छात्र मेधावी थे और सब दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला पा रहे थे। इनमें कई विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो सिर्फ विदेशी छात्रों से कमाई करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंटों की कमाई का जरिया बने हुए थे। युवाओं को छात्र के रूप में इन देशों में भेजकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। दरअसल, धीरे-धीरे छात्रों और उनके अभिभावकों की हकीकत का अहसास होता चला गया। उन्होंने महसूस किया कि वे मोटा पैसा खर्च करके जैसे-तैसे छिड़ी तो पा सकते हैं, लेकिन ये नौकरी व ग्रीन कार्ड की गारंटी नहीं है। कुछ छात्र किसी तरह छोटे-मोटे काम-धंधे करके अपनी पढ़ाई का खर्चा व घर का कर्जा उतारने का जुगाड़ जरूर कर लेते थे।

धीरे-धीरे अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों के दुराग्रहों व उनकी प्राथमिकताओं ने छात्रों को

खुदुरी जमीन के यथार्थ से रूबरू करा दिया। छात्रों को एजेंटों ने जो सबजगमग दिखाए थे, उनकी हकीकत सामने आने लगी। इसके अलावा कोरोना काल के बाद विश्वकी अर्थव्यवस्थाएं, नौकरी के आकर्षक प्रस्तावों में कमी, थोड़ा मिलने में हो रही दिक्कतें, इन देशों के गरीे चमड़ी वाले लोगों के भारतीयों पर बड़े हमलों ने छात्रों में मोहभंग की स्थिति उत्पन्न कर दी।

बीते साल अमेरिका में कई भारतीय छात्रों पर नस्लीय हमले हुए। कई छात्रों की हत्या हुई और अनेक घायल हुए। कनाडा व ब्रिटेन में भारत विरोधी अभियानों तथा कनाडा में जस्टिन ट्रुडो के भारत विरोधी रवैये ने भी छात्रों का मोहभंग किया। वैसे देखा जाए तो विदेशी युवा अर्जित करने के बजाय हम हर साल अरबों रुपये इन देशों को भेज रहे थे। दूसरी ओर छात्रों के विदेश जाने के मोहभंग होने का सार्थक पलू यह भी है कि अब ये प्रतिभाएं देश में रहकर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं।

कुदरत का नियम है कि अपनी उर्वरा भूमि में ही पौधे अनुकूल वातावरण के चलते खिलते-निखरते हैं। ये हमारे नीति-नियंताओं की विफलता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले विश्वविद्यालय नहीं दे पाये। सामान्य शिक्षा में कौशल विकास के गुण को विकसित नहीं कर पाए। छात्रों में सरकारी नौकरियां पाने की लालसा को रचनात्मक हिकलप नहीं दे पाये। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर आईटी से जुड़ी लगभग बड़ी कंपनियों को भारतीय प्रतिभाएं चला रही हैं। आखिर क्यों हम भारतीय मेधाओं को देश में ही वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, कि वे नई खोजों व अनुसंधान से देश को लाभान्वित कर सकें। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। यदि हम उनकी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी बड़ी नाकामी है। देश के सप्ताधीशों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि क्यों छात्रों में विदेश जाने की होड़ लगी रहती थी। छात्रों को अनुकूल वातावरण देकर ही विकसित भारत के संकल्प पूरे हो सकते हैं।

बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव से जुड़े जीवन-संकट



ललित गर्ग

भारत में इस समय गर्मी एवं हीट वेव का प्रकोप ब?ता जा रहा है, खासकर उत्तर भारत के अनेक राज्यों विशेषतः गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में अप्रैल के प्रारंभ में ही बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी, कई शहरों में पारा 44-45 डिग्री तक चढ़ गया है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो चिन्ताजनक होने के साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सबब है। लगातार बढ़ती गर्मी के आंकड़े एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के परिणामों और इसकी वजह से ख? हुए संकट को ही दर्शा रहे हैं। अधिक तापमान पानी की गंभीर कमी का कारण बन सकता है, कृषि को प्रभावित कर सकता है और विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में के दुष्परिणाम से ही गर्मी एवं लू का प्रकोप लोगों की सेहत, कार्य-क्षमता और उत्पादकता पर गंभीर खतरा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, देश का करीब 75 फीसदी कार्यलब कृषि और निर्माण क्षेत्र में गर्मी का सीधे सामना करने वाले श्रम पर निर्भर करता है। इसके मुताबिक साल 2030 तक गर्मी के प्रकोप से जु?ी उत्पादकता में गिरावट की वजह से दुनिया भर में कुल होने वाली नौकरियों के नुकसान में अकेले भारत का योगदान करीब 43 फीसदी तक हो सकता है।

इस बार ब?ती गर्मी के पुराने सारे रेकॉर्ड तो? देने की चेतावनी दी जा रही है जो हमारे लिए चौंकाने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। गुजरात एवं राजस्थान के अनेक स्थानों पर अभी से गर्मी इतनी तेज है कि कुछ ही दिनों में धरती त्वे की तरह तपने लगेगी। पानी की कमी, बिजली कटौती और गर्म लू के कारण बीमारी के हालात गंभीर हो सकते हैं। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल होगा। सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहें कि हीटवेव के लिए अबतक कुछ हम, हमारी

सु वि धा वा दी जीवनशैली और हमारा विकास का नजरिया भी जिम्मेदार है। आज शहरीकरण, विकास के नाम पर प्रकृति को विकृत करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं गांवों में हो या शहरों में आंख मींचकर कंक्रीट के जंगल खड़े करने की हो? के दुष्परिणाम से ही गर्मी कहर बरपाती है और प्रकृति एवं पर्यावरण की विकरालता के रूप में सामने आती हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं किया। अब विकास एवं सुविधाओं और प्रकृति के बीच सामंजस्य की और ध्यान देना होगा, अन्यथा आने वाले साल और अधिक चुनौती भरें होंगें। कंक्रीट के जालों से लेकर हमारे दैनिक उपयोग के अधिकांश साधन एवं विकास की भ्रामक सोच तापमान को ब?ने वाले हैं।

विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के वरूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अल विकासशील देशों को नसीहत दे रहे हैं। निश्चित रूप से ब?ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो



पहले ही जीवनशैली से जु? रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। ऐसा ही संकट वृद्धों के लिये भी है, जो बेहतर चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवनयापन कर रहे हैं। वैसे एक तथ्य यह भी है कि मौसम के चरम पर आने, यानी अब चाहे बा? हो, शीत लहर हो या फिर लू हो, मरने वालों में अधिकांश गरीब व कामगार तबक के लोग ही होते हैं। जिनका जीवन गर्मी में खालि निकले बिना या काम किये बिना चल नहीं सकता। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्हें मौसम और गरीबी दोनों मारती हैं।

प्रतिवर्ष धरती का तापमान ब? रहा है। आबादी ब? रही है, जमीन छेटी पड़ रही है। हर चीज की उपलब्धता कम हो रही है। आवसीजन की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा तापमान में लगातार असंतुलन सामान्य घटना नहीं है,

जिसका दायरा अब वैश्विक हो गया है। भले ही कोई इस विनाशकारी स्थिति को तात्कालिक घटना कहकर खारिज कर दे लेकिन जमीनी सच्चाई यह है की बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स का पिघलना और हीट वेव बहुत बड़े वैश्विक खतरों की आहट है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कथित विकास की बेहेशी से दुनियां को जागना प?ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 'तीसरा ध्रुव' कहे जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, आज हिमालय से बर्फ के पिघलने की गति 'रितल आइस एज' के वक्त से

औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटल आइस एज का काल 16वीं से 19वीं सदी के बीच का था। इस दौरान बड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकों की मानें, तो हिमालय के ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर के मुकाबले ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पूरी तरह से पिघलने पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर शिफ्ट हो जाएगी। इससे पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। पृथ्वी के सभी महाद्वीप आंशिक रूप से पानी के भीतर समा जाएंगे। भारी मात्रा में जैव-विकथता को हानि पहुंचेगी। पृथ्वी पर रहने वाली हजारों प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी पर एक विनाशकारी एवं विकराल स्थिति का उद्भव होगा। इसके साथ ही दुनियां भर में करो?ों की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भाड़ेंड कराना प?ेगा। दुनियाभर में कूलिंग सिस्टम्स यानी एयरकंडीशन की मांग

भारत की सड़कों पर सुरक्षा को बनाना होगा सशक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। पैराकोट की सहायक कंपनी पैरासेफ, यात्रा के सभी साधनों में सुरक्षा को प्राथमिकता देकर मोबिलिटी को पुनः परिभाषित करने के लिए समर्पित है। सड़क सुरक्षा ट्रस्ट्स में क्रांतिकारी बदलाव लाने और सड़क जागरूकता को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूप में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध, पैरासेफ ने जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक शोध किया है और श्वेत पत्र प्रकाशित किए हैं।भारत की सबसे जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों में से एक है- सड़क सुरक्षा। 2022 में, सड़क दुर्घटनाओं ने दुखद रूप से 1.68 लाख लोगों की जान ले ली। वाहन टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, मूल कारण अभी भी बने हुए हैं जो हैं- अज्ञानता (65 प्रतिशत) और कानूनों का कमजोर अमल (52 प्रतिशत)। पैरासेफ की रिपोर्ट इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालती है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में सड़क सुरक्षा जागरूकता और अभ्यास की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। पैरासेफ के सीईओ राजेश पोद्दार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कहा, 'सड़क सुरक्षा का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है; यह जीवन बचाने के बारे में है। उद्योग जगत के अग्रणी के रूप में, सभी स्टेकहोल्डरों- सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। निष्कर्षों से पता चलता है कि सड़क सुरक्षा तैयारियों में अंतराल को घटाने की तकता आवश्यकता है। पैरासेफ में, हम मानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा किट और हार्नेस जैसे आवश्यक सुरक्षा उपार्यों के बारे में जागरूकता और पहुँच दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकती है। अब समय आ गया है कि हम भारत की सड़कों पर हर यात्रा को सुरक्षित और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट हों।

इन्फिनित्स ने पेश किया नोट 50एस 5जी.

मुंबई, एजेंसी। आधुनिक समय के स्मार्टफोन ब्रांड इन्फ़िनित्स ने आज भारत में अपनी फ्लैगशिप डिवाइस – नोट 50एस 5जी. लॉन्च की यह एक पावरहाउस डिवाईस है जो डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में अपेक्षाओं को बढ़ा देगी। इस फ्लैगशिप डिवाइस ने अत्याधुनिक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी और 144हर्ट्ज़ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ भारत के सबसे स्लिम स्मार्टफ़ोन' के रूप में एक नया मानक स्थापित कर दिया है। नोट 50एस 5जी. आज से फ्लिपकार्ट पर तीन शानदार रंगों मरीन ड्रिफ्ट ब्लू (वीगन लेडर), टाइटेनियम ग्रे (मैटेलिक फ़िनिश), बरगुंडी रेड (मैटेलिक फ़िनिश) में 14.9 रुपये (सभी ऑफ़र सहित) के विशेष मूल्य में उपलब्ध है।इन्फ़िनित्स इंडिया के सीईओ अनिश कपूर ने कहा इन्फ़िनित्स में हम अपने हर लॉन्च के साथ यूज़र्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपने पिछले स्मार्टफ़ोन, नोट 50एक्स 5जी. में हमने यूज़र्स के फ़ीडबैक के आधार पर सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड किया और एक्सओएस 15 पेश किया। हमारे इस कक्रम को ग्राहकों ने काफी सराहा, जिससे निर्माण प्रक्रिया में यूज़र्स को शामिल करने का हमारा विश्वास मजबूत हुआ। नोट 50एस 5जी. में हमने प्रीमियम सीएमएफ़ू बेहतरीन परफॉर्मेंस और सेगमेंट के सबसे स्लिम 144हर्ट्ज़ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमने मानकों को और अधिक बढ़ा दिया है।इसमें मॉडियूटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ 5500एमएएच की बैटरी दी गई है। इसलिए यह पूरे दिन हर स्वाप, स्ट्रीम और स्कॉल के साथ स्मूथ परफॉर्मेंस प्रदान करता है। एआई-आधारित पर्सनलाइजेशन, एक्सओएस 15 और वन-टैप इन्फ़िनित्स एआई से स्मार्ट और इंट्यूटिव अनुभव प्राप्त होता है, वहीं 64एमपी सोनी आईएमएक्स682 कैमरा एवं मिलिटरी-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी से बेहतरीन स्टार्ईल और फ़ंशशन प्राप्त होता है।भारत में डिजिटल-फ़र्स्ट एक्सपेरिंस के लिए निर्मित, नोट 50एस 5जी. में परफॉर्मेंस, ख़ूबसूरती और बेहतरीन मूल्य एक ही पैकेज में मिल रहा है। यह लॉन्च उपयोगी इनोवेशन प्रदान करने के हमारे सफ़र की एक बड़ी कामयाबी है।

सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड ने भारतीय फूड एन्ड रिटेल सेक्टर में एक नया कदम उठाते हुए माजघर नाम से अपना पहला आउटलेट शुरू किया

अहमदाबाद एजेंसी। भारत के फूड एन्ड रिटेल लेन्डस्केप में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड ने एसडीएफ के सहयोग से, अहमदाबाद के सोला रोड के पास सत्ताधर चार रास्ता के नजदीक मेमनगर में माजघर ब्रांड नाम से अपना पहला आउटलेट लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, उनका दुष्टिकोण भी बहुत प्सुचरिस्टिक है। वे अगले 12 महीनों के भीतर भारत के शीर्ष शहरों में 12 माजघर आउटलेट ओपन करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपये तक का स्ट्रेटेजिक ईन्वेस्टमेन्ट करने की योजना बनाई है और 23.5 करोड़ रुपये का रेवन्यू जनरेट करने का लक्ष्य रखा है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि लोग वर्तमान में अधिक गुणवत्ता की मांग कर रहे हैं, इसलिए वे प्रीमियम गुणवत्ता की आपूर्ति करने में सक्षम होने की दृष्टि से बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इस आउटलेट में चावल, कटोला, प्रिज़न-ड्राई व्यंजन, ग्लूटेन-फ्री प्रोडक्ट्स, मसाले, पापड़, चाय मसाला, मुखवास और जामुन शहद जैसी स्वादिष्ट प्रीमियम वस्तुओं का अमृता संग्रह है। उनका प्रत्येक उत्पाद भारत के अनूठे स्वाद के साथ-साथ नई पीढ़ी के बदलते स्वाद की भी पूरा करता है। चर्लू विकास के साथ-साथ एसडीएफ और सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड की नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी है। कंपनियां सक्रिय रूप से मध्य पूर्व, आफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों में अपने निर्यात नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। उनके वैश्विक पोर्टफोलियो में फ़ेश वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, अनाज, मेन्गो पल्प और सल्फर रहित गुड़ का चयन भी शामिल है, जो शुद्धता, पोषण और पारंपरिक भारतीय स्वाद पर अधिक केंद्रित है।

वित्तीय स्वतंत्रता, आपके अपने तरीके से - टाटा एआईए ने स्मार्ट सुरक्षा और विकास के लिए लॉन्च किया शुभ पलेव्सी इनकम प्लान

मुंबई, एजेंसी। जीवन सपनों से भरा है- घर खरीदना, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाना, शानदार छुट्टियों की योजना बनाना या चिंता मुक्त सेवानिवृत्ति का आनंद लेना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुरक्षा काफी नहीं है, आपको चाहिए एक ऐसी योजना जो आपको आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहे। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, टाटा एआईए लाइफ इश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (टाटा एआईए) ने टाटा एआईए शुभ फ्लेक्सी इनकम प्लान लॉन्च किया है। यह एक नया जीवन बीमा बचत समाधान है जो वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति बनाने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण देता है। इस प्लान को आपके साथ विकसित होने के लिए डिज़ाइन किया गया – लचीलापान इसकी विशेषता है। शुभ फ्लेक्सी इनकम प्लान एक नॉन-लिव्कड, पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा बचत योजना है। इसमें आपको अपनी अनूठी आकांक्षाओं के आधार पर अपनी वित्तीय योजना को अनुकूलित करने का अधिकार मिलता है। यह योजना आपको शुरूआत से ही लचीलापान देते हुए, तीन अनुकूलित विकल्प प्रदान करती है, यह हर विकल्प विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंडोमेंट विकल्प – दीर्घकालिक बचत बनाने के लिए आदर्श है। इसमें आपको योजना के अंत में एकमुश्त भुगतान मिलता है।

20 वरिष्ठ आईएस अधिकारियों की नई पदस्थापना, मप्र कैडर के मनोज गोविल कैबिनेट सचिवालय में सचिव नियुक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 20 वरिष्ठ आईएसएसअधिकारियों की नई पदस्थापना की है। मप्र कैडर के मनोज गोविल कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश कैडर के दूरे अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, विवेक अग्रवाल, हरिरंजन राव, पल्लवी जैन गोविल के विभागों में फेरबदल कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीओपीटी द्वारा इस संबंध में आज जारी आदेश के अनुसार आज जारी आदेश में केंद्र सरकार में नवंबर 2025 तक लगभग सभी प्रमुख रिक्रियों को भर दिया गया है।

नवनियुक्त अधिकारियों की सूची इस प्रकार है: वर्तमान युवा मामले सचिव मीता राजीव लोचन को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 31.05.2025 को सेवानिवृत्त होने पर ए.नौरजा का स्थान लेंगे।

के मोसेस चालई को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभागके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, वे गृह मंत्रालय के तहत अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सचिव हैं। वे अली रजा रिजवी की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में, का अतिरिक्त प्रभार अरुणिश चावला के पास है।

मध्य प्रदेश कैडर में 1991 बैच के आईएसएस अधिकारी व्यय सचिव मनोज गोविल को कैबिनेट सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। उन्हें वंदना गुरनानी के स्थान पर कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किया गया। वंदना गुरनानी को कैबिनेट सचिवालय से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वे सुमिता डावरा की जगह लेंगी, जो 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हुई। राजिव पुहानी, वर्तमान में राज्य सभा सचिवालय के सचिव, को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें अतुल कुमार तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 30 जून, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। आशीष श्रीवास्तव को गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे के मोसेस चालई की जगह लेंगे। वर्तमान में श्रीवास्तव अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान नागरिक उड्डयन सचिव वुम्लुनगंम वुलनाम को वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग का सचिव

नहीं थम रहें सोने के दाम, आज भी तेजी, चांदी की चमक पड़ी फीकी

मुंबई, एजेंसी। प्रैल के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में हर दिन कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप भी आज बाजार जाकर सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आज के ताज़ा भाव जरूर जान लें, क्योंकि कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आज शनिवार, 19 अप्रैल 2025 को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने के दाम में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे इसका भाव 97,730 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 89,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। अगर आप हल्के गहनों या आभूषणों में निवेश करना चाहते हैं, तो 18 कैरेट सोना आज 73,314 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है। जहां एक ओर सोने की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं चांदी में थोड़ी गिरावट देखी गई है। आज चांदी के भाव में 100 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है, जिससे इसका नया रेट 99,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। यह अब भी एक लाख रुपए प्रति किलो से नीचे बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कि विभिन्न शहरों में आज के सोने के 18, 22 और 24 कैरेट के लेटेस्ट रेट क्या हैं।

18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव: दिल्ली रुपए 73,120 प्रति 10 ग्राम, कोलकाता और मुंबई रुपए 72,990 प्रति



नियुक्त किया गया है। वे मनोज गोविल का स्थान लेंगे। निकुंज बिहारी धल जो वर्तमान में इसी कैडर में हैं, को संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 30 जून 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति पर उमंग नरुला का स्थान लेंगे।

राकेश कुमार वर्माको भारत के चुनाव आयोग में महानिदेशक (प्रशिक्षण) के पद को अस्थायी रूप से उन्नत और पुनः नामित करके भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, वह जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। अनुराधा ठाकुर को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अगले केंद्रीय सचिव के रूप में चुना गया है। वे श्रम में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने पर अजय सेठ से कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान में, वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं।

राजेश अग्रवाल को वाणिज्य विभाग का अगला केंद्रीय सचिव चुना गया। उन्हें वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया (इन-सीट), जहां वे अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे 30 सितंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने पर निवर्तमान वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वे संजय मल्होत्रा का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश कैडर में 1994 बैच के अधिकारी विवेक अग्रवाल को संस्कृति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। वे गोविंद मोहन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालने के बाद पद खाली कर दिया

मप्र में बन रहा पहला आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क रेलवे और एयरपोर्ट से मिलेगा सीधा जुड़ाव

भोपाल। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनने जा रहा है, जो देशभर के उद्योगों के लिए एक नई दिशा तय करेगा। यह पार्क रेलवे और एयरपोर्ट दोनों से जुड़ा होगा, जिससे माल परिवहन और निर्यात की प्रक्रिया और अधिक आसान और तेज़ हो जाएगी। इस लॉजिस्टिक पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी है। माल को रेलमार्ग से सीधे पार्क तक लाया जा सकेगा और कस्टम की सभी औपचारिकताएं यहीं पूरी कर दी जाएंगी। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे कंटेनर सीधे हवाई अड्डे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के व्यवसायियों को निर्यात प्रक्रिया में बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। वे दो बार इंदौर दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सागौर से लॉजिस्टिक पार्क तक नई रेलवे लाइन

टीवीएस मोटर कंपनी ने किया अपग्रेडेड टीवीएस अपाचे आरआर 310 का अनावरण

बैंगलुरु, एजेंसी। दुनिया में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों की अग्रणी निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी (टीवीएसएम) ने सुपर प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाकल कैटेगरी में अपनी मुख्य पेशकश- अपग्रेडेड टीवीएस अपाचे आरआर310 का अनावरण किया है। 2025 एडीशन ओबीडी-2बी नियमों के लिए कम्प्लायन्ट है। टीवीएस अपाचे सीरीज की 20वीं सालगिरह और दुनिया भर में 6 मिलियन उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार करने की उपलब्धि का जश्न मनाते हुए कंपनी यह नया एडीशन लेकर आई है। टीवीएस अपाचे आरआर 310 एक मास्टरपीस है जो पिछले चार दशकों से टीवीएस रेसिंग में अपना प्रभुत्व बनाए हुए है।

ताज लेकफ्रंट भोपाल के हाउस ऑफ मिंग में पेश हुआ त्यंजनों का नया एक्साइटिंग मेन्यू



गए हैं। सीफूड प्रेमियों के लिए स्कैलप्स, क्रैब्स, प्रॉन्स और लॉबस्टर का भी जबरदस्त सलेक्शन है। वहीं मीठे के शौकीनों के लिए एलीमेंट्स और वाइल्ड

इंदौर संभाग के एक वर्तमान तथा एक पूर्व कलेक्टर को मिलेगा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार



इंदौर। इंदौर संभाग सहित पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। इंदौर संभाग के बड़वानी जिले के पूर्व कलेक्टर डॉ. फर्टिंग राहुल हरिदास और झाबुआ जिले की वर्तमान कलेक्टर नेहा मीना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2025 को दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान करेंगे।

कलेक्टर डॉ. फर्टिंग राहुल हरिदास को समग्र विकास श्रेणी और कलेक्टर नेहा मीना को इस्तिरेशाल ब्लॉक्स प्रोग्रामकैटेगरी में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान दिया

भोपाल में आइशर प्रो एक्स छोटे ट्रकों के लिए नया डीलरशिप शुरू किया

भोपाल। वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (वीईसीवी) की एक व्यावसायिक इकाई आइशर ट्रक्स एंड बस ने अपने नए लॉन्च किए गए आइशर प्रो एक्स छोटे ट्रकों के लिए एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप का उद्घाटन किया। भोपाल में स्थित सक्सेस ऑटो कमर्शियल की यह नई 3एस डीलरशिप ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो वाहन खरीदने और सेवा प्रक्रिया के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करती है। इंटरएक्टिव डिजिटल डिस्प्ले से सुसज्जित यह डीलरशिप ग्राहकों को आइशर प्रो एक्स रेंज की गहन जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे सही वाहन चयन कर सकें और आइशर की नवाचार और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का अनुभव प्राप्त करें। रमेश राजगोपालन, कार्यकारी उपाध्यक्ष, ग्राहक सेवा, रिटेल उत्कृष्टता और नेटवर्क विकास, वीईसीवी ने कहा मध्य प्रदेश आइशर का घर है, और हमें भोपाल में नए लॉन्च किए गए आइशर प्रो एक्स रेंज के लिए यह एक्सक्लूसिव डीलरशिप शुरू करते हुए गर्व हो रहा है। यह नई डीलरशिप हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हम स्मार्ट, सस्टेनेबल और कस्टमर-फर्स्ट सोल्यूशंस के माध्यम से अंतिम मील लॉजिस्टिक्स के भविष्य को आकार देना चाहते हैं।



का उद्घाटन किया है, जिससे इस प्रोजेक्ट की और गति मिली है। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांझल के अनुसार, यह पार्क कुल 250 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है और इसकी लागत 1100 करोड़ रुपये आंकी गई है। पार्क का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में वेयरहाउस, ऑफिस स्पेस, कोल्ड स्टोरेज और एक 5 स्टार होटल का

निर्माण किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में पार्क का विस्तार होगा और अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह लॉजिस्टिक पार्क न केवल इंदौर बल्कि पूरे मालवांचल क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होगा। यहां तैयार माल का निर्यात तेजी से किया जा सकेगा, जिससे उद्योगों को समय और लागत दोनों में बचत होगी। इस आधुनिक पार्क के निर्माण से पीथमपुर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।

ताज लेकफ्रंट भोपाल के जनरल मैनेजर, विशाल शर्मा ने कहा, झीलों की इस नगरी में, ताज ब्रांड के सिग्नेचर रेस्टोरेंट हाउस ऑफ मिंग के ज़रिए हम शहरवासियों को पैन-एशियन व्यंजनों के फूड लवर्स को पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस लॉन्च के चलते हाउस ऑफ मिंग कुछ खास डाइनिंग एक्सपीरियंस भी पेश किया जा रहा है —जिसमें थ्रीड मैनेजर, बीरेन्द्र बिष्ट ने भी कहा हम सबको आमंत्रित करते हैं कि वे ताज लेकफ्रंट भोपाल के अपने पसंदीदा डाइनिंग डेस्टिनेशन—हाउस ऑफ मिंग—में नए मेनू का जायका लें।

प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित, 27 अप्रैल से छह मई तक नामांकन होंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए 27 अप्रैल से छह मई तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस दौरान नामांकन पर दवे-आपत्ति 28 अप्रैल से 7 मई तक स्वीकार



किए जाएंगे। नामांकन की जांच 7 से 9 मई तक की जाएगी और नामांकन को अंतिम रूप 11 मई को दिया जाएगा। 18 से 35 वर्ष की आयु वाले ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवायसी) एप के जरिए से वोटिंग होगी। सदस्यता के साथ ही वोटिंग का मिलेगा अधिकार। पहली बार ब्लाक

अध्यक्ष का भी सीधे चुनाव होगा। सदस्य प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया लगभग पांच महीने में पूरी होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही युवक कांग्रेस से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है।

जिम में बेहोश होकर गिरा शख्स सीपीआर के बाद भी नहीं बची जान



जबलपुर। यहां जिम में एक्सरसाइज करते-करते अचानक एक व्यक्ति बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिम में मौजूद लोग उसे सीपीआर देकर उठाने की कोशिश करते रहे लेकिन वह दोबारा कभी नहीं उठा और उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरत में है। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें लोगों को अचानक से किसी एक्टिविटी को करते-करते गिरकर मरते हुए देखा गया है। दरअसल, मामला जबलपुर के गोरखपुर इलाके का बताया जा रहा है। यहां मौजूद गोल्डजिम में एक्सरसाइज करते-करते एक व्यक्ति बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 52 साल के यतीश सिंहई के रूप में हुई है। यतीश रोजाना की तरह करीब 6-45 बजे जिम में मशीनों से एक्सरसाइज कर रहा था। इसी बीच अचानक दिल का दौरा पड़ने से वह नीचे गिर गया।

हार्ट अटैक आने का वीडियो सामने आया

एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक आने का वीडियो भी सामने आया है, जो जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में यतीश को अचानक से गिरते हुए देखा जा सकता है। हार्ट अटैक आते ही जिम के ट्रेनर और वहां मौजूद अन्य लोग भाकर यतीश के पास पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने सीपीआर और अन्य तरीकों से यतीश को बचाने की कोशिश की। वीडियो में यतीश सिंहई को जिम के ट्रेनर और अन्य साथी उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें शहर के भंडारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने यतीश को मृत घोषित कर दिया।

भोपाल में एलपीजी वितरकों की सरकार से 7 मांगें

राष्ट्रीय अधिवेशन में पदाधिकारी बोले- पहले निवेदन करेंगे, फिर अनिश्चित काल का आंदोलन

भोपाल। भोपाल के समन्वय भवन में शनिवार को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स (सिलेंडर वितरकों) का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें देशभर से गैस वितरक शामिल हुए। इस बैठक में वितरकों के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रेड की मुख्य समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे राष्ट्रीय पदाधिकारी सरकार के सामने रख सके।



कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के. के. धौरतिया ने कहा कि, हम सरकार से भीख नहीं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसलिए पहले निवेदन करेंगे, फिर आंदोलन। इस मौके पर संगठन द्वारा वितरकों की चुनौतियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

पदाधिकारी बोले- वितरकों का कमीशन बेहद कम

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि एलपीजी वितरकों को वर्तमान में दिया जाने वाला कमीशन बेहद कम है। इसे कम से कम 7150 प्रति सिलेंडर किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन, वितरण में लगने वाले वाहनों की सुविधा आदि की लागत कोविड के बाद से काफी बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑयल कंपनियां %कॉम्पीटीशन एक्ट% का उल्लंघन कर रही हैं। जब वे कहती हैं कि ग्राहकों को जबरदस्ती गैस नहीं देनी है, तो वही कंपनियां वितरकों पर दबाव क्यों डालती हैं?

संगठन के सात सूत्रीय मांग पत्र में यह मांगें

- कमीशन में बढ़ोतरी
- ऑयल कंपनियों से अनुबंध की समीक्षा
- एमडीजी (मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन्स) एक्ट को समाप्त करना
- लीकेज समस्याओं की जवाबदेही से वितरकों को मुक्त करना
- आवश्यकता से अधिक सिलेंडर का स्टॉक देना
- उज्ज्वला योजना में पैनल्टी का मुद्दा

सेल्स ऑफिसरों के दबाव को कम करना

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि ये मांगें पूरी नहीं हुईं तो संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। उन्होंने कहा, अब इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। हर व्यक्ति 50 वितरकों को साथ लाए, ताकि मंत्रालय तक इसकी गूंज पहुंचे। देशभर में 25,000 वितरक हैं।

स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे हैं पर्याप्त बजटीय प्रावधान: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

टेलीमेडिसिन सुविधा के विस्तार के लिए निर्देश, दतिया में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर माह तक डॉक्टरों की नई भर्ती सुनिश्चित कर सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्राथमिक, उप-स्वास्थ्य एवं सामुदायिक केंद्रों सहित आरोग्य मंदिरों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दतिया जिले के अपने अल्प प्रवास के दौरान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने टेलीमेडिसिन सेवा से जिले के सभी प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक उन्नत विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर गाँव-गाँव में बैठकर मरीजों को परामर्श दे सकेंगे। इससे मरीजों को बार-बार जिला अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके समय



एवं धन की भी बचत होगी।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को बताया कि जिला अस्पताल में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिक अलार्म

जैसी नवीन पहल प्रारंभ की गई है। साथ ही कलेक्टर श्री माकिन ने नव निर्मित दतिया एयरपोर्ट की व्यस्थाओं के संबंध में भी उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को अवगत कराया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने माँ पीताम्बरा के दर्शन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दतिया के अल्प प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचकर माँ पीताम्बरा के दर्शन किए एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण एवं सुख-समृद्धि की कामना की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्राचीन वन खण्डेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक भी किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ परिसर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र सरकार की



«प्रसाद योजना» के अंतर्गत शक्तिपीठ परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु स्वीकृत 44.24 करोड़ रुपए की परियोजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्व. शिवम गोस्वामी को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढाढस

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दतिया के गंज राजगढ़ मार्ग में दिवंगत युवा संगीतकार शिवम गोस्वामी के निवास पहुंचे। उन्होंने सड़क दुर्घटना में असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोककुल परिवार को ढाढस बंधाया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में परिवार के साथ है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के



लिए प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल दुर्घटना में घायल आदित्य तिवारी के निवास भी पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।



महापौर मालती राय ने आज वाई 33 बल्लभ नगर में लगभग 28 लाख की लागत से सी सी रॉड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी , एम आई सी सदस्य आर के सिंह बघेल, मंडल अध्यक्ष सोनू पालीवाल पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

प्रदेश में नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी, 1 मई से ट्रांसफर बैन हटेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार 1 मई से ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध हटा सकती है और इसके साथ ही नई तबादला नीति भी लागू हो जाएगी। लंबे समय से अटकी इस नीति का झूफट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट से इसी महीने इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई तबादला नीति के तहत मई और जून का माह तबादलों के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने जनवरी में कुछ शर्तों के साथ उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों को तबादले का अवसर दिया था, लेकिन इसके दायरे में बहुत कम कर्मचारी ही आ सके। तब से ही कर्मचारी संगठनों द्वारा व्यापक तबादला प्रक्रिया की मांग की जा रही थी, जिस पर अब अमल होता दिख रहा है। ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है। जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।

विभागीय मंत्री की अनुशांसा पर होगा ट्रांसफर : जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशांसा पर आधारित होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है। किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे। बता दें मध्य प्रदेश में तीन साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी।

साइबर वारियर्स की तैनाती, एमपी को मिले 5 टेक्नो-कमांडो, शुरु होगा डिजिटल क्राइम का सफाया

भोपाल। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत तैयार की गई साइबर कमांडो फोर्स अब एक्शन मोड में आ चुकी है। इस योजना के पहले चरण में देशभर से चुने गए 350 अधिकारियों को हार्ड-टेक ट्रेनिंग देकर साइबर कमांडो के रूप में तैयार किया गया है।



इनमें मध्यप्रदेश से 6 अफसर शामिल थे, जिनमें से 5 ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और राज्य को सौंप दिए गए हैं, जबकि एक अधिकारी की ट्रेनिंग अभी भी जारी है।

देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ली तकनीकी दक्षता

साइबर कमांडो को देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास, गांधीनगर और पुणे में एडवंस साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क फॉरेंसिक, डिजिटल ट्रैकिंग और एथिकल हैकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्हें साइबर मुख्यालय में तैनात किया गया है, जहां वे प्रदेश की डिजिटल सुरक्षा के लिए काम करेंगे।

ऑनलाइन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

साइबर एंडीजी ए. साई मनोहर ने जानकारी दी कि ये साइबर कमांडो अब प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी जैसे अपराधों पर शिकंजा कसेंगे। इसके अलावा, सरकारी वेबसाइट्स को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने और डिजिटल आपात स्थिति से निपटने की रणनीतियों में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

5000 साइबर कमांडो का लक्ष्य

मध्यप्रदेश का दूसरा बैच भी तैयार

- सरकार की योजना के मुताबिक, पूरे देश में कुल 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे।
- पहले चरण में 6 महीने की गहन ट्रेनिंग के बाद 350 कमांडो फोर्स में शामिल किए गए।
- अब मध्यप्रदेश के 39 सब-डिस्ट्रिक्टों का दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, जो जल्द ही प्रशिक्षण के लिए नामित संस्थानों में भेजे जाएंगे।